

 सत्यमेव जयते	केंद्रीयकर आयुक्त (अपील)		
	O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GENERAL TAX, वस्तु एवं सेवा GST Building, 7 th Floor, कर भवन Near Polytechnic, सातवीं मंजिल, पोलिटिकानिक के पास, Ambavadi, Ahmedabad-380015 आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015		
 079-26305065			टेलिफैक्स : 079 - 26305136

692010 6924

क फाइल संख्या : File No : **V2/69/GNR/2018-19**

ख अपील आदेश संख्या : Order-In-Appeal No.: **AHM-EXCUS-003-APP-105-18-19**

दिनांक Date : **01-10-2018** जारी करने की तारीख Date of Issue: **1-11-2018**

श्री उमाशंकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

Passed by **Shri Uma Shanker** Commissioner (Appeals) Ahmedabad

C. Jile

ग अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III आयुक्तालय द्वारा जारी मूल आदेश :
PLN-AC-STX-13/2017 दिनांक : **28-03-2018** से सृजित

Arising out of Order-in-Original: **PLN-AC-STX-13/2017**, Date: **28-03-2018** Issued by:
 Assistant Commissioner, CGST, Div: Palanpur, Gandhinagar Commissionerate,
 Ahmedabad.

घ अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता

Name & Address of the **Appellant** & Respondent

M/s. Ambica Carriers

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

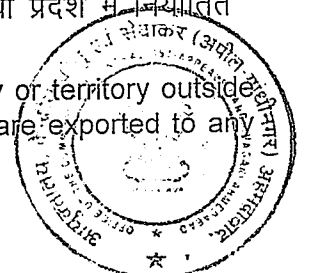
(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रक्रिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.



- (ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।
- (C) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

ध अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35- णबी/35-इ के अंतर्गत:-

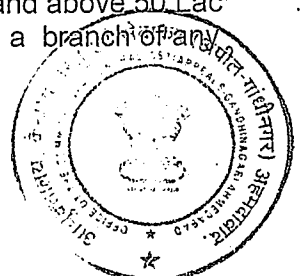
Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016.

To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इ.ए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से रेखाकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any



nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्टेट) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1988 की धारा 34फ के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-2) अधिनियम 2014(2014 की संख्या 29) दिनांक: 06.08.2014 जो की वित्तीय अधिनियम, 1998 की धारा 23 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "माँग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- (ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होंगे।

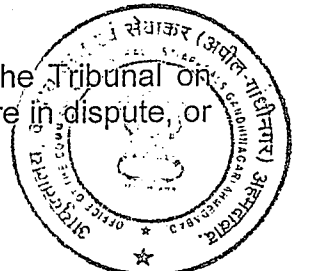
For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores, Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

→ Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(6)(i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

(6)(i) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



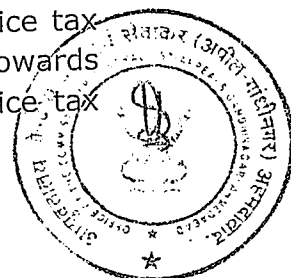
ORDER IN APPEAL

This appeal has been filed by M/s Ambica Carrier, Nova Vando, Chanasma, Dist. Patan, Gujarat [for short-'appellant'] against Order-in-Original No.PLN-AC-STX-13/2017 dated 28.03.2018 [for short-'impugned order'] passed by the Assistant Commissioner of Central GST, Palanpur Division, Gandhinagar Commissionerate [for short-'the adjudicating authority'].

2. The facts briefly are that the appellant is registered and engaged in providing Manpower Supply services, Maintenance and Repairs Services. During the course of audit of the records of the appellant, it was noticed that they provides services to various plants and educational institutes of M/s Nirmal Ltd, in relation to management of transport vehicles, manpower supply (i.e drivers, cleaners and repairing staff, loading and unloading on vehicles and repairs and maintenance of vehicles owned by M/s Nirmal Ltd). As per terms and condition of agreement between the appellant and M/s Nirma Ltd, the appellant is paid monthly charges for maintenance of vehicles and salary of manpower supply and other statutory payment of the staff; that the expenditure incurred by the appellant are reimbursed by M/s Nirmal Ltd. It appeared that the appellant had collected various charges from M/s Nirma Ltd and is considering only few charges for the payment of service tax and considering the remaining charges as reimbursement of expenses incurred by them, as treating themselves as providing services on behalf of M/s Nirma Ltd; that for the period upto 30.06.2012, they were required to pay tax on full taxable value and for the period thereafter they were required to pay tax on 25% of the taxable value in view of the provisions of NotofictionNo.30/2012 dated 20.06.2012. Therefore, a show cause notice dated 10.08.2016 pertains to the period of 20011-12 to 2013-14 was issued to them for recovery of amount of Rs.48,26,449/- towards payment of service tax on gross amount received from M/s Nirmal Ltd. The show cause notice also proposes recovery of interest on such short payment and imposition of penalty under Section 77(2) and 78 of Finance Act, 1994. This notice was adjudicated vide impugned order by the adjudicating authority wherein he confirmed the charges and the demand along with interest and further imposed penalty under sections 77 and 78 of the Finance Act, 1994.

3. In the appeal filed by the appellant before Commissioner (Appeals), they raised the following contentions:

- It is not the case of the department that service tax has not been paid on the services rendered by them; that they paid service tax on the Manpower Supply service and the fixed amount towards supervision charges. The case of the department that service tax



has not been paid on the reimbursement charges and the adjudicating authority has held that amount reimbursed is consideration towards the service rendered.

- The agreement between the appellant and M/s Nirmal Ltd provides that they shall be paid the expenses incurred at actual towards vehicles owned by service receiver and expenses such as diesel, petrol etc incurred on vehicle are not related to service rendered. Therefore the tax confirmed is not only incorrect, illegal and contrary to the provisions of Section 67 of FA and service tax valuation Rules.
- Higher Appellate Authority and the Court have consistently held that reimbursement expenses, which has no nexus with the services so provided and incurred on behalf of the service provider could not be included in the valuation of the service as per the provisions of Section 67 of FA. The appellant relies on various case laws in support of their arguments.

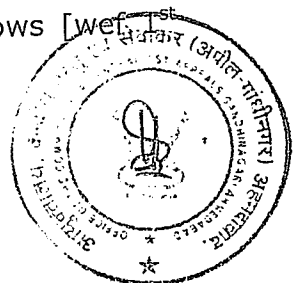
8. Personal hearing in the case was held on 25.7.2018 wherein Shri Vikram Singh Jhala, Authorized representative, appeared on behalf of the appellant and reiterated the submissions/grounds of appeal. He also submitted that the disputes in the present appeal were settled issues and submitted copies of the various orders.

9. I have gone through the facts of the case, the grounds of appeals and the oral contentions raised during the course of personal hearing. I find that the question to be decided is whether the appellant is liable for service tax on the gross amount received by them from service recipient M/s Nirmal Ltd.

10. I find that the allegation against the appellant is that they were considering only few charges for the payment of service tax from the amount received from M/s Nirma Ltd and considering the remaining charges as reimbursement of expenses incurred by them. It is the argument of the appellant that as per agreement between the appellant and M/s Nirmal Ltd, the appellant shall be paid the expenses incurred at actual towards vehicles owned by M/s Nitma Ltd and expenses such as diesel, petrol etc incurred on vehicle are not related to service rendered. The adjudicating authority based on a combined reading of Section 67 of the Finance Act, 1994 read with Rule 5 of the Service Tax (Determination of Value), Rules, 2006, held that all consideration received by a service provider towards any service, should be included in the gross taxable value further holding that the said charges are not recovered on actual basis.

11. Now Section 67 of the Finance Act, 1994, states as follows [we] :
May, 2006] :

"67. Valuation of taxable services for charging service tax.



(1) Subject to the provisions of this Chapter, where service tax is chargeable on any taxable service with reference to its value, then such value shall,

(i) in a case where the provision of service is for a consideration in money, be the gross amount charged by the service provider for such service provided or to be provided by him;

(ii) in a case where the provision of service is for a consideration not wholly or partly consisting of money, be such amount in money as, with the addition of service tax charged, is equivalent to the consideration;

(iii) in a case where the provision of service is for a consideration which is not ascertainable, be the amount as may be determined in the prescribed manner.

(2) Where the gross amount charged by a service provider, for the service provided or to be provided is inclusive of service tax payable, the value of such taxable service shall be such amount as, with the addition of tax payable, is equal to the gross amount charged.

(3) The gross amount charged for the taxable service shall include any amount received towards the taxable service before, during or after provision of such service.

(4) Subject to the provisions of sub sections (1), (2) and (3), the value shall be determined in such manner as may be prescribed.

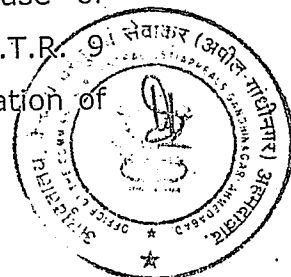
Explanation: For the purpose of this section,

(a) "consideration" includes any amount that is payable for the taxable services provided or to be provided;

(b) "money" includes any currency, cheque, promissory note, letter of credit, draft, pay order, travelers cheque, money order, postal remittance and other similar instruments but does not include currency that is held for its numismatic value;

(c) "gross amount charged" includes payment by cheque, credit card, deduction from account and any form of payment by issue of credit notes or debit notes and book adjustment, and any amount credited or debited, as the case may be, to any account, whether called "Suspense account" or by any other name, in the books of accounts of a person liable to pay service tax, where the transaction of taxable service is with any associated enterprise."

Section 67 of the Finance Act, 1994, clearly provides that in the valuation of taxable services, nothing more or nothing less than the consideration paid as quid pro quo for the service, can be brought to charge. Further, "consideration" means any amount that is payable for the taxable services provided or to be provided. As per details submitted by the appellant i.e. copy of invoices and statement of expenses incurred towards vehicles expenses, it appears that the total amount collected from M/s Nirma Ltd is nothing to do with the taxable services provided by the appellant. The question of demanding tax on the said amount by including it in the value of taxable service is legally not correct. This gets further strengthened in terms of the judgment of the Hon'ble High Court of Delhi in the case of Intercontinental Consultants & Technocrats Pvt. Ltd. [2013 (29) S.T.R. 91 (Del.)], wherein the Court held Rule 5 of the Service Tax (Determination of



Value), Rules, 2006, to be ultra vires. The Hon'ble Delhi High Court in the case of Intercontinental Consultants & Technocrats Pvt. Ltd. [2013 (29) S.T.R. 9 (Del.)], wherein on the question of the constitutional validity of Rule 5 of the Service Tax (Determination of Value) Rules, 2006 to the extent it includes re-imbusement of expenses in the value of taxable services for the purposes of levy of service tax, the Court held as follows:

18. Section 66 levies service tax at a particular rate on the value of taxable services. Section 67(1) makes the provisions of the section subject to the provisions of Chapter V, which includes Section 66. This is a clear mandate that the value of taxable services for charging service tax has to be in consonance with Section 66 which levies a tax only on the taxable service and nothing else. There is thus inbuilt mechanism to ensure that only the taxable service shall be evaluated under the provisions of 67. Clause (i) of sub-section (1) of Section 67 provides that the value of the taxable service shall be the gross amount charged by the service provider "for such service". Reading Section 66 and Section 67(1)(i) together and harmoniously, it seems clear to us that in the valuation of the taxable service, nothing more and nothing less than the consideration paid as quid pro quo for the service can be brought to charge. Sub-section (4) of Section 67 which enables the determination of the value of the taxable service "in such manner as may be prescribed" is expressly made subject to the provisions of sub-section (1). The thread which runs through Sections 66, 67 and Section 94, which empowers the Central Government to make rules for carrying out the provisions of Chapter V of the Act is manifest, in the sense that only the service actually provided by the service provider can be valued and assessed to service tax. **We are, therefore, undoubtedly of the opinion that Rule 5(1) of the Rules runs counter and is repugnant to Sections 66 and 67 of the Act and to that extent it is ultra vires.** It purports to tax not what is due from the service provider under the charging Section, but it seeks to extract something more from him by including in the valuation of the taxable service the other expenditure and costs which are incurred by the service provider "in the course of providing taxable service". What is brought to charge under the relevant Sections is only the consideration for the taxable service. By including the expenditure and costs, Rule-5(1) goes far beyond the charging provisions and cannot be upheld. It is no answer to say that under sub-section (4) of Section 94 of the Act, every rule framed by the Central Government shall be laid before each House of Parliament and that the House has the power to modify the rule. As pointed out by the Supreme Court in *Hukam Chand v. Union of India*, AIR 1972 SC 2427 :-

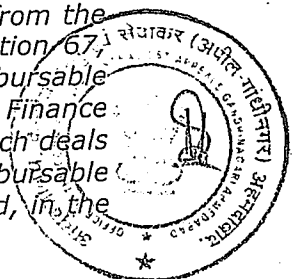
"The fact that the rules framed under the Act have to be laid before each House of Parliament would not confer validity on a rule if it is made not in conformity with Section 40 of the Act."

Thus Section 94(4) does not add any greater force to the Rules than what they ordinarily have as species of subordinate legislation

[emphasis supplied]

The department feeling aggrieved by the aforesaid judgment, filed an appeal before the Hon'ble Supreme Court of India. The Supreme Court in the departmental appeal in the case of Intercontinental Consultants & Technocrats Pvt. Ltd. [2018 (10) G.S.T.L. 401 (S.C.)], held as follows:

29. In the present case, the aforesaid view gets strengthened from the manner in which the Legislature itself acted. Realising that Section 67, dealing with valuation of taxable services, does not include reimbursable expenses for providing such service, the Legislature amended by Finance Act, 2015 with effect from May 14, 2015, whereby Clause (a) which deals with 'consideration' is suitably amended to include reimbursable expenditure or cost incurred by the service provider and charged, in the



course of providing or agreeing to provide a taxable service. **Thus, only with effect from May 14, 2015, by virtue of provisions of Section 67 itself, such reimbursable expenditure or cost would also form part of valuation of taxable services for charging service tax.** Though, it was not argued by the Learned Counsel for the Department that Section 67 is a declaratory provision, nor could it be argued so, as we find that this is a substantive change brought about with the amendment to Section 67 and, **therefore, has to be prospective in nature.** On this aspect of the matter, we may usefully refer to the Constitution Bench judgment in the case of Commissioner of Income Tax (Central)-I, New Delhi v. Vatika Township Private Limited [(2015) 1 SCC 1] wherein it was observed as under :

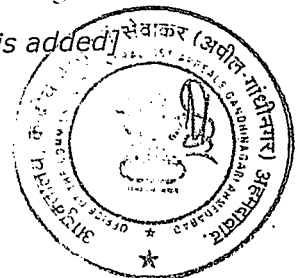
"27. A legislation, be it a statutory Act or a statutory rule or a statutory notification, may physically consists of words printed on papers. However, conceptually it is a great deal more than an ordinary prose. There is a special peculiarity in the mode of verbal communication by a legislation. A legislation is not just a series of statements, such as one finds in a work of fiction/non-fiction or even in a judgment of a court of law. There is a technique required to draft a legislation as well as to understand a legislation. Former technique is known as legislative drafting and latter one is to be found in the various principles of "interpretation of statutes". Vis-a-vis ordinary prose, a legislation differs in its provenance, layout and features as also in the implication as to its meaning that arise by presumptions as to the intent of the maker thereof.

28. Of the various rules guiding how a legislation has to be interpreted, one established rule is that unless a contrary intention appears, a legislation is presumed not to be intended to have a retrospective operation. The idea behind the rule is that a current law should govern current activities. Law passed today cannot apply to the events of the past. If we do something today, we do it keeping in view the law of today and in force and not tomorrow's backward adjustment of it. Our belief in the nature of the law is founded on the bedrock that every human being is entitled to arrange his affairs by relying on the existing law and should not find that his plans have been retrospectively upset. This principle of law is known as *lex prospicit non respicit* : law looks forward not backward. As was observed in Phillips v. Eyre [(1870) LR 6 QB 1] , a retrospective legislation is contrary to the general principle that legislation by which the conduct of mankind is to be regulated when introduced for the first time to deal with future acts ought not to change the character of past transactions carried on upon the faith of the then existing law.

29. The obvious basis of the principle against retrospectivity is the principle of "fairness", which must be the basis of every legal rule as was observed in L'Office Cherifien des Phosphates v. Yamashita-Shinnihon Steamship Co. Ltd. Thus, legislations which modified accrued rights or which impose obligations or impose new duties or attach a new disability have to be treated as prospective unless the legislative intent is clearly to give the enactment a retrospective effect; unless the legislation is for purpose of supplying an obvious omission in a former legislation or to explain a former legislation. We need not note the cornucopia of case law available on the subject because aforesaid legal position clearly emerges from the various decisions and this legal position was conceded by the counsel for the parties. In any case, we shall refer to few judgments containing this dicta, a little later."

30. As a result, we do not find any merit in any of those appeals which are accordingly dismissed.

[emphasis added]



12. Article 141 of the Constitution of India states that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. As, it has been held by the Hon'ble Supreme Court of India that reimbursable expenses cannot form a part of the valuation of taxable services, the question of adding reimbursable expenditure to the gross amount charged in terms of Section 67 of the Finance Act, 1994, for the period prior to 14.5.2015 simply does not arise more so since the present dispute is pertaining to the period 2006-07 and 2007-08. Thus, the demand confirmed by the adjudicating authority vide the impugned OIO, along with interest, and penalty under sections 77 and 78 in respect of this portion is accordingly, set aside.

13. In view of the foregoing, the impugned order is set aside and the appeal is allowed.

14. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
14. The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.

उमाशंकर

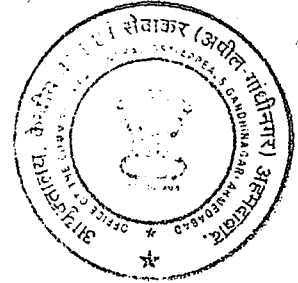
(उमा शंकर)

आयुक्त (अपील्स)

Date : 19.2.2018

Attested

2/23/18
(Mohan V.V)
Superintendent (Appeal),
Central Tax,
Ahmedabad.



By RPAD.

To,
M/s Ambica Carrier,
Nova Vando, Chanasma,
Dist. Patan, Gujarat

Copy to:-

1. The Chief Commissioner, Central Tax, Ahmedabad Zone .
2. The Commissioner, Central Tax, Gandhinagar Commissionerate.
3. The Assistant Commissioner, Central Tax Division-Planpur, G'nagar Commissionerate.
4. The Assistant Commissioner, System, Central Tax, Gandhinagar Commissionerate.
5. Guard File.
6. P.A.

